











**सम्पादकीय**

स्लिम समाज की समस्याएँ  
इन्कार नहीं, 'गंभीर' रो  
के खतरनाक उपचार की  
कोशिश में विपक्षी नेता

मुस्लिम समाज का समस्याआ  
से इन्कार नहीं, 'गंभीर' रोग  
के खतरनाक उपचार की  
कोशिश में विपक्षी नेता

तब केवल बंगाल ही नहीं, देश के तत्कालीन प्रांतों (असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बैंग्ला, पंजाब, ओडिशा, मद्रास सहित), जो आज खंडित भारत का हिस्सा है, वहाँ भी 80 से 100 प्रतिशत मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। इस परे प्रपंच में व्याप्त समस्याओं से इनकार नहीं, लेकिन ममता, राहुल और लालू सरीखे जिस तरह इसका उपचार कर रहे हैं, वह विकराल बीमारियों को ही पैदा करेगा। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण की सांविधानिक वैधता पर जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। 22 मई को अदालत ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद मुस्लिमों को अन्य पिछावर्ग (ओबीसी) आरक्षण के तहत जारी प्रमाणपत्रों को असांविधानिक बताकर रद्द कर दिया। यह पहली बार नहीं है, जब किसी राजनीतिक दल ने स्थापित आरक्षण व्यवस्था में डाका डालकर सभी मुसलमानों को गरीब-वर्चित बताकर अवैध आरक्षण देने का प्रयास किया है। आखिर बाबर-बाबर ऐसी कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर न्यायमूर्ति तप्पबत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथ की खंडपीठ द्वारा व्यक्त टिप्पणी में मिल जाता है। उनके अनुसार, 'मुसलमानों के कुछ वर्गों का "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए" ओबीसी आरक्षण दिया गया। जिन मुस्लिम वर्गों को आरक्षण दिया गया, उन्हें राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था ने एक वस्तु और 'वोटबैक' के रूप में इस्तेमाल किया। यह संविधान और लोकतंत्र का अपमान है।' इस निण्य का प्रदेश की मुख्यमंत्री और तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया है। आखिर इसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल की वर्तमान आबादी 10 करोड़ से अधिक है, जिसमें सात करोड़ हिंदू और 2.7 करोड़ मुसलमान हैं। लोकनीति-सौण्डीएस के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल के पक्ष में मतदान किया था, जो 2016 में 51 प्रतिशत था। यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में से 13 में मुस्लिम आबादी 32-64 प्रतिशत तक है, जबकि 20 सीटों पर हिंदूओं की आबादी 35-50 प्रतिशत है। रिभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1951 की जनगणना में प्रदेश की कुल जनसंख्या 2.63 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम 50 लाख, यानी 19 प्रतिशत थे। 2011 की जनगणना में उनकी आबादी बढ़कर 3.45 करोड़ से अधिक, यानी 27 प्रतिशत हो गई। वर्तमान आंकड़ा वर्ष 1941 में संयुक्त बंगाल की मुस्लिम आबादी—29.5 प्रतिशत वरें काफी निकट है। यहाँ अविभाजित बंगाल में वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि तब इस क्षेत्र के 95 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिम लीग को गोट देकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।

तब केवल बंगाल ही नहीं, देश के तत्कालीन प्रांतों (असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बैंग्ला, पंजाब, ओडिशा, मद्रास सहित), जो आज खंडित भारत का हिस्सा है, वहाँ भी 80 से 100 प्रतिशत मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। इस परे प्रपंच में व्याप्त समस्याओं से इनकार नहीं, लेकिन ममता, राहुल और लालू सरीखे जिस तरह इसका उपचार कर रहे हैं, वह विकराल बीमारियों को ही पैदा करेगा। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण की सांविधानिक वैधता पर जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। 22 मई को अदालत ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद मुस्लिमों को अन्य पिछावर्ग (ओबीसी) आरक्षण के तहत जारी प्रमाणपत्रों को असांविधानिक बताकर रद्द कर दिया। यह पहली बार नहीं है, जब किसी राजनीतिक दल ने स्थापित आरक्षण व्यवस्था में डाका डालकर सभी मुसलमानों को गरीब-वर्चित बताकर अवैध आरक्षण देने का प्रयास किया है। आखिर बाबर-बाबर ऐसी कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर न्यायमूर्ति तप्पबत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथ की खंडपीठ द्वारा व्यक्त टिप्पणी में मिल जाता है। उनके अनुसार, 'मुसलमानों के कुछ वर्गों का "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए" ओबीसी आरक्षण दिया गया। जिन मुस्लिम वर्गों को आरक्षण दिया गया, उन्हें राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था ने एक वस्तु और 'वोटबैक' के रूप में इस्तेमाल किया। यह संविधान और लोकतंत्र का अपमान है।' इस निण्य का प्रदेश की मुख्यमंत्री और तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया है। आखिर इसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल की वर्तमान आबादी 10 करोड़ से अधिक है, जिसमें सात करोड़ हिंदू और 2.7 करोड़ मुसलमान हैं। लोकनीति-सौण्डीएस के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल के पक्ष में मतदान किया था, जो 2016 में 51 प्रतिशत था। यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में से 13 में मुस्लिम आबादी 32-64 प्रतिशत तक है, जबकि 20 सीटों पर हिंदूओं की आबादी 35-50 प्रतिशत है। रिभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1951 की जनगणना में प्रदेश की कुल जनसंख्या 2.63 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम 50 लाख, यानी 19 प्रतिशत थे। 2011 की जनगणना में उनकी आबादी बढ़कर 3.45 करोड़ से अधिक, यानी 27 प्रतिशत हो गई। वर्तमान आंकड़ा वर्ष 1941 में संयुक्त बंगाल की मुस्लिम आबादी—29.5 प्रतिशत वरें काफी निकट है। यहाँ अविभाजित बंगाल में वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि तब इस क्षेत्र के 95 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिम लीग को गोट देकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।

तब केवल बंगाल ही नहीं, देश के तत्कालीन प्रांतों (असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बैंग्ला, पंजाब, ओडिशा, मद्रास सहित), जो आज खंडित भारत का हिस्सा है, वहाँ भी 80 से 100 प्रतिशत मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। इस परे प्रपंच में व्याप्त समस्याओं से इनकार नहीं, लेकिन ममता, राहुल और लालू सरीखे जिस तरह इसका उपचार कर रहे हैं, वह विकराल बीमारियों को ही पैदा करेगा। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण की सांविधानिक वैधता पर जो आशंका व्यक्त की थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है। मुस्लिम समाज में व्याप्त समस्याओं से इनकार नहीं, लेकिन ममता, राहुल और लालू सरीखे जिस तरह इसका उपचार कर रहे हैं, वह विकराल बीमारियों को ही पैदा करेगा। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण की सांविधानिक वैधता पर जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। 22 मई को अदालत ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद मुस्लिमों को अन्य पिछावर्ग (ओबीसी) आरक्षण के तहत जारी प्रमाणपत्रों को असांविधानिक बताकर रद्द कर दिया। यह पहली बार नहीं है, जब किसी राजनीतिक दल ने स्थापित आरक्षण व्यवस्था में डाका डालकर सभी मुसलमानों को गरीब-वर्चित बताकर अवैध आरक्षण देने का प्रयास किया है। आखिर बाबर-बाबर ऐसी कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर न्यायमूर्ति तप्पबत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथ की खंडपीठ द्वारा व्यक्त टिप्पणी में मिल जाता है। उनके अनुसार, 'मुस्लिम वोटबैक के लिए स्वर्योषित सेक्यूरिटर दलों द्वारा कट्टरपंथी मुसलमानों को तुष्ट करना कितना घातक है, यह गांधीजी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए जाने से स्पष्ट है। तब मजहबी कारणों से अधिकांश मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन से कटे हुए थे। उन्हें ब्रिटनियों के खिलाफ एकजुट करने हेतु गांधीजी ने उस घोर मजहबी और कट्टरपंथी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका भारतीय मुस्लिमों से कोई संबंध नहीं था। गांधीजी की सोच थी कि इससे राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य को बल मिलेगा। परंतु मुस्लिम कट्टरपंथीयों ने इसे भारत में इस्लामी वर्चस्व की पुनर्वापसी का उपक्रम बना लिया। अंततोगत, पाकिस्तान का जन्म हुआ। क्या स्वतंत्रता के बाद खंडित भारत में इस मजहबी तुष्टीकरण पर लगाम लगी? नहीं। जब सामाजिक सुधार हेतु 1955-56 में हिंदू कोड बिल लाया गया, तब मुस्लिम समादाय को उनकी मजहबी मान्यताओं (हलाल-तीन तलाक सहित) के साथ छोड़ दिया गया। जब 1985-86 में सर्वीच न्यायालय ने शाहबानों मामले में मुस्लिम महिलाओं को मध्यकारी न मानसिकता से बाहर निकालने वाला फैसला सुनाया, तब कट्टरपंथीयों के हिस्से के प्रदर्शन और 'इस्लाम खतरे में' के उद्घोष के आगे नतमस्तक होते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में बहुमत के बल पर अदालत का निण्य पलट दिया। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बता दिया।

19 पङ्गोसियों को चुनौती देने की हठधर्मिता, राष्ट्रपति जिनपिंग का अहंकार जिम्मेदार

पाठ्यपात्र शो जिनापेंग का ठंडर्मिता के कारण बीन पड़सी शों के लिए बड़ी चुनौती है। माइबर दुनिया में चीन की आजिशें अक्सर चर्चा में रहती हैं। उसके योजनाकार भारत के पैदा कर सकते हैं, जिन्हे मानव गतिविधियों की तरह तैयार किया गया है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने को मिला है। वर्तमान सरकार के कुछ विदेश-

कर सकते हैं, जिन्हे मानव  
वेदियों की तरह तैयार किया  
है। मौजूदा लोकसभा चूनाव  
परान भी ऐसा देखने को मिला  
र्तमान सरकार के कुछ विदेश-

गणज्ञों शेर साबित हुड़। इसलेण  
पीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब गैर-  
वारपंरिक युद्ध करने की कोशिश  
नव रही है। उसके निशाने पर विशेष  
न्प से विदेश में बसा सिख समुदाय  
सफलता ओर  
चीन चिंतित हो  
भारत और चीन  
युद्ध की फिलहाल  
नहीं है, लेकिन

सफलता और आधिक सुधार से चीन चिंतित हो उठा है। हालांकि भारत और चीन के बीच खुले युद्ध की फिलहाल कोई आशंका नहीं है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण



ह, जिनके 'आधिकारक' रूप से लाखों फॉलोअर्स हैं। चीन ने सोशल मीडिया के जरिये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन वह पकड़ा गया और उसने आहत होने का नाटक किया। मेटा जैसी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी के सतर्क होने और दुर्भावनापूर्ण खातों को निष्क्रिय करने के बाद चीन (और उसका अनुयायी पाकिस्तान) सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले प्रमुख देश के रूप में उभरा है। यानी सोशल मीडिया को चीन ने पूरी तरह से एंटी-सोशल (असामाजिक) बना दिया। वर्ष 2020 में गलवान की घटना (जो चीन की भयंकर भूल थी) के बाद उसकी चर्चित सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलएल)

आर कम्बा-कम्बा के प्रयासों से बच सकते। चीनी स्पष्ट धमातिर रणनीति अपनाई। लेकिन कश्मीर में जब उसकी दाल नहीं गली और कश्मीर के लोगों को राष्ट्रीय पुण्यधारा में जुड़ने के आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिखने लगे, तो चीन ने अपना ध्यान विदेश में बसे छहरांथी सिखों की तरफ लगाया। उसकी यह साजिश भी विफल होने लाली है, क्योंकि भारत की पर्यटवस्था आसमान छू रही है और दुनिया भारत के साथ दोस्ती का फायदे समझ रही है। पिछले तीन वर्षों में चीन ने भारत पर काफी आर्थिक दबाव बनाया, उसके बावजूद वहामारी पर काबू पाने में हमारी

आर कभा-कभार जमान हड्पन  
के प्रयासों से इन्कार नहीं कर  
सकते। चीनी राजनयिकों ने  
स्पष्ट धमकियां देने की  
रणनीति अपनाने की कोशिश  
की और मेजबान देशों को  
नाराज किया, जिससे चीन की  
छवि को नुकसान ही पहुंचा।  
पूर्व मंगोलियाई राष्ट्रपति, जो  
शी से 30 बार मिल चुके हैं, ने  
लिखा कि शी दिखाते हैं कि  
‘व्यक्तिगत रूप से करिशमाई  
होने के साथ विश्व मंच पर  
खतरनाक और निरंकुश होना  
संभव है। वह दुष्ट भी हो सकते  
हैं।’ अपने सभी 19 पड़ोसियों  
को चुनौती देने की हठधर्मिता  
की चीन भारी कीमत चुका रहा  
है, जिसके लिए उसके राष्ट्रपति  
का अहंकार जिम्मेदार है।

नैन्सी ने कान्स में गुलाबी रंग का जो गाउन पहना, उसे उसने खुद भी पत्रकारों के सवालों के जवाब हिंदी में ही दिए और हिंदी भाषी टीवी मैकेनिक है और मां एक फैटरी में काम करती है। उसका भी पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा हिंदी में भी दी जा सकती कंपनियां महिलाओं को कपड़े सिलना सिखाने के लिए स्कूल भी चलाती

सिला था। इसमें एक हजार मीटर कपड़ा और बनाने में एक महीना लगा। जिस कान्स में बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज दुनिया के मशहूर डिजाइनर्स के बेहद महंगे कपड़े पहनती हैं, वहां नैन्सी ने खुद का सिला गाउन पहनकर सबको चकित कर दिया। मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि वह उसके लिए आपनी कपड़े सिले। फ्रांस में हुआ कान्स कल्पना केंटवल इस बार इसलिए हद खास रहा कि इसमें उत्तर देश के बागपत जिले के गांव रनावा की तेरईस साल की लड़की न्सी त्यागी ने सफलता के झड़े बढ़ दिए। इसे वहां छठ एजेंसी ने तरफ से भेजा गया था। बेहद रीरो परिवेश से आई इस लड़की को कपड़े सिलने का बेहद शौक। यह तमाम सेलिब्रिटीज को खक्कर कपड़े सिलनी थी और उसके गोटे इंस्टाग्राम पर लगाती थी। कुरु में उसे बहुत ट्रोल भी किया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं दिया। धीरे-धीरे इसकी फैन गॉलोइंग बढ़ी और आज इसके साढ़े बाठ लाख फॉलोअर्स हैं। अब हो रहकता है और भी बढ़ गए हॉ।

**कपड़ा और बनाने में एक महीना लगा। जिस कान्स में बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज दुनिया के मशहूर डिजाइनर्स के बेहद महंगे कपड़े पहनती हैं, वहां नैन्सी ने खुद का सिला गाउन पहनकर सबको चकित कर दिया। मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि वह उसके लिए आपनी कपड़े सिले। नैन्सी ने फ्रांस में**



रोने पर गर्व प्रकट किया। उसने कहना था कि मां की हाङ्ग-तोड़



सेलिब्रिटीज दुनिया के मशहूर डिजाइनर्स के बेहद महंगे कपड़े पहनती हैं, वहां नैस्सी ने खुद का सिला गाउन पहनकर सबको चकित कर दिया। मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि वह उसके लिए भी कपड़े सिले। नैस्सी ने फ्रांस में

## एण्टंग्र के

मंग्रेजी न आने पर भी वह वहां जा सकी, जहां जाने के सपने बहुत से थोड़े देखते हैं। शुरू में उसके पिता भी उसका विरोध किया था, मगर गान्स की सफलता के बाद अब वह भी उसका हौसला बढ़ाने लगे हैं। बताते चलें कि नैस्सी के पिता का स्वास्थ्य न खराब हो जाए। वह उनके लिए ही कुछ करना चाहती थी। नैस्सी बारहवीं के बाद दिल्ली आ गई थी। वह यूपीएससी करना चाहती थी, मगर पैसे की तंगी के साथ अंग्रेजी न आने की समस्या भी थी। हालांकि उसे बाद में यह

पहली गलती पार्टी प्रणाली का भ्रष्टाचार है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक पार्टी के सहयोगियों के प्रति जगवादहेद होते हैं। भारतीय राजनीति आज इस मॉडल से को नजरअंदाज कर प्रियंका गांधी में रही है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली को हमने खो देंगे, बिना किसी हंगामे के अपना किया जाता है। इस तरह के ऐसे व्यक्ति को चना जाएगा जो को डराने और चुप कराने के लिए स्तर, दृष्टिमिष्ठी और विलुप्त होती जैव विविधता की वजह से करोड़ों भारतीयों की आजीविका और सेहत में पहली बार केंद्र में सत्ताखढ़द दल

ANALYSTS' PREDICTIONS

www.west.com

हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि हमारी राजनीतिक कमियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने



स वजह से कांग्रेस अध्यक्ष लिलाकर्जुन खड़गे ने गुलबगां की अपनी पुरानी सीट अपनै दामाद को दी, जबकि उनका एक बेटा पहले ही कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल बैंहार में, सपा उत्तर प्रदेश में और ऐएमके तमिलनाडु में ऐसी पाठियां, जो एक ही परिवार के नियंत्रण

याया, उससे हम कितने अलग धानमंत्री ऋषि सुनक के सामने धर्म-पंथ नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता केर स्टार्म किसी नीतिक परिवार से नहीं आते वो दोनों आज जिस मुकाम पर हां अपनी मेहनत और पार्टी व्ययोगियों के समर्थन से हैं। भी वे समर्थकों का विश्वास

बहुत कम हा भारत का जयव्यवस्था  
मिश्रित है और इसके पर्यावरणीय  
रिकॉर्ड विनाशकारी रहे हैं। आर्थिक  
तौर पर भारत के सबसे 'समुद्र  
शहर' बैंगलुरु में जल संकट और  
भारत के 'वैशिख उत्थान' वाले शहर  
नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की उच्च दर  
इस बात का प्रतीक है कि हमने  
संसाधनों का कितना दुरुपयोग किया  
है। जैसा कि मैंने पहले लिखा है,  
हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा पर्यावरण  
संकट है। जहरीली हवा, गिरता जल

# दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति है रेलवे

पूरा दुनिया में रेलवे सरकार का सबसे बड़ी चुनौती है। निजी कंपनियों का संसार आकाश से पाताल तक फैल गया है। मगर सरकारें उन्हें रेलवे में निवेश को राजी नहीं कर पाती। रेलवे दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति थी, मगर यह आर्थिक तौर पर सबसे अभिशप्त कारोबार भी है। 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अगुआई में एक कमीशन बना और इसकी सिफारिश पर 1924 में रेलवे के बजट को सरकार के बजट से अलग कर दिया गया। निजी रेल वंपनियों का सरकारीकरण हो गया। आजादी के बाद भारत की निजी रेलवे पूरी तरह सरकारी हो गई। 2017 में रेलवे बजट आम बजट का हिस्सा बन गया। अब फिर भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोशिश शुरू हो रही है। भारत में चुनावी चकलुस के बीच जनता को यह पता नहीं चला कि भारतीय रेल यात्री किराये की कमाई में पिछड़ गई है। रेलवे का पैसेंजर राजस्व बीते साल में उस गति से भी नहीं बढ़ा, जिस रफतार से भारत की जीडीपी (महांगाई सहित यानी नॉमिनल) बढ़ी है। वर्दे भारत ट्रेनों को कामयाब बनाने के लिए बीते साल किराये भी घटाए गए थे, मगर रेलवे को महंगे टिकट लेने वाले यात्री नहीं मिल रहे। दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने निजी ट्रेनें चलाने की योजना रोक दी थी। 30,000 करोड़ का टैंडर लौट गया। यह भारत में रेलवे के निजीकरण की पहली सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश थी, रुट तय हो गए थे। निजी कंपनियां और सरकार के बीच कमाई के बंटवारे का फॉर्मूला बन गया, मगर कंपनियों ने भारत के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर यानी रेलवे में दिलचस्पी ही नहीं ली। वर्ष 2022 में सरकार ने रेलवे की संपत्तियां बेचने की कोशिश की। कोई ग्राहक नहीं आया। रेलवे के कुछ विभाग और प्रतिष्ठान बंद करने की तैयारी है, धाटा कम करने या नए संसाधन जुटाने की हर जुगत और मुंह गिर पड़ा। बात एक दशक में रेलवे बजट खत्म करने से लेकर निजीकरण तक, तमाम कोशिशों के बाद भी इस महाकाय गतिमान बुनियादी ढांचे की बैसाखियां हटती ही नहीं। रेलवे के घाटे का दुख दूर ही नहीं होता। अलबत्ता भारत अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में रेल सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। निजी कंपनियों का संसार आकाश से पाताल तक फैल गया है। मगर सरकारें उन्हें रेलवे में निवेश के लिए राजी नहीं कर पाती। रेलवे दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति थी, मगर यह आर्थिक तौर पर सबसे अभिशप्त कारोबार भी है। आइए, टाइम मशीन में विराजिए। चलते हैं करीब 200 साल पीछे रेलवे के चमत्कारी दिनों में... आपको अपनी सीट पर एक उपन्यास रखा मिला होगा। जब तक हम उडान भरते हैं, आप इसका आनंद लीजिए। स्कॉटिश कवि और व्यंग्यकार डब्ल्यू. ई. आइटन का यह व्यंग्य उपन्यास 1845 में आया था। इसका शीर्षक है-हात वी गॉट अप द मुनमचकिन रेलवे? हम यूरोपीय इतिहास के जिस युग में जा रहे हैं, वह रेलवे बबल यानी रेलवे में भारी निवेश और नुकसान का दौर है। यह उपन्यास उस वक्त का प्रतिनिधि दस्तावेज माना जाता है। यह भीड़ देख रहे हैं। यह दुनिया के इतिहास के सबसे अनोखे मोड़ का गवाह बन रही है। यह 1830 है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच यात्री ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन के आने से पहले तक लोग घोड़ों वाली बगधी पर यात्रा करते थे। पहली यात्री रेल खूब कामयाब हुई। उदयोगपतियों ने रेलवे में पंजी झोकनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की सरकार ने एक साथ 3,000 से अधिक रेल लाइनों को मंजुरी दे दी है। ब्रिटेन की आर्थिक हवा रेल क्रांति के किस्सों से महक रही है। निजी कंपनियां और बैंक रेलवे में निवेश का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। आप 21वीं सदी से आए हैं, तो आपको उस तरह के अंथी निवेश में खतरों का एहसास है।

भी पता चला कि यौपीएससी की परीक्षा हिंदी में भी दी जा सकती है। लेकिन एक बार में चयन हो जाए, यह जरुरी नहीं है। वैसे भी गांव वाले माता-पिता से कहते रहते थे कि क्या लड़की पर पैसे खर्च कर रहे हो, लड़के पर करो। मगर नैन्सी ने एक कैमरा खरीदा और सोशल मीडिया का रुख किया और सहारा लिया अपने शौक यानी कपड़ों को सिलने का। बचपन में वह गड़ियों के लिए कपड़े बनाती थी, फिर अपने लिए बनाने लगी। नैन्सी की मदद करने के लिए उसकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए। उसका कहना है कि उसकी मां ने हमेशा उसे बहुत सहारा दिया। इसलिए वह भी उनके लिए कुछ करना चाहती है। कुछ मिलाकर देखा जाए, तो सिलाई मशीन उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। भारत में अरसे से सिलाई मशीन की सहायता से न जाने कितनी महिलाओं ने अपना और अपने प्रियराव का पेट पाला है। परिं के न रहने पर बहुत-सी महिलाएं कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती रही हैं। ऐसी बहुत-सी महिलाओं को मैं निजी तौर पर जानती हूँ। कई तो रिश्ते में भी हैं। एक जमाने में सिलाई मशीन कंपनियां महिलाओं को कपड़े सिलना सिखाने के लिए स्कूल भी चलाती थीं। नैन्सी के मामले में सिलाई मशीन ने उसकी गरीबी तो दूर की ही, उसके सपनों को भी पूरा किया। यह बात भी उसके अभूतपूर्व आत्मविश्वास को दर्शाती है कि उसने एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खुद के बनाए कपड़े पहने और खुब प्रशंसा हासिल की। उससे एक संवाददाता ने जब यह पूछा कि कोई तुमसे अगर अभी शादी करने के बारे में कहे, तो क्या करोगी? उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया- भगा दूंगी। नैन्सी का कहना है कि सोशल मीडिया पर सफलता के लिए कन्टेंट में दम होना चाहिए। फिर उसने यह भी कहा कि चार-पांच दिन से कुछ नहीं सिला है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं किया है। नैन्सी से प्रेरणा लेकर उसके रिश्तेदारों में कई लड़कियां ऐसा करना चाहती हैं। बात भी सही है, अपने बीच से यदि कोई सफल होता है, तो बाकी औरों के लिए भी सफलता के नए द्वार खोलता है। लड़कियों के मामले में तो यह बात और भी सही है। नैन्सी आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, अपने प्रयतनें से उसने राह के सारे कांटे हटा दिए हैं।

स्तर, दूषित मिट्टी और विलुप्त होती जैव विविधता की वजह से करोड़ों भारतीयों की आजीविका और सेहत खतरे में पड़ गई है और ये भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे औद्योगिक और आर्थिक संसाधन टिकाऊ हैं? कई दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इसमें सबसे अधिक बनती है। उसका कहना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उसके बाद से स्थिति और खराब होती गई। हम जिसे सांप्रदायिक समस्या कहते हैं, वह भी कोई नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए, उन्हें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए आश्वस्त किया था कि पाकिस्तान में जो भी अधिकार दिए गए हैं, वही समान नागरिक अधिकार यहां भी दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा गया। धर्मों के बीच की यह खाई राजीव गांधी के शासनकाल में बढ़ती गई, जिसके उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, दोनों के बीच कट्टरता को बढ़ावा दिया। 2014 के बाद से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना कई गुना बढ़ गई, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अपनी हिंदू बहुसंख्यकवादी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर दिया था। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में धर्म का बोलबाल बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री ने खुद को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजे गए उस हिंदू राजा की तरह दिखाया, जो हिंदुओं की सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों ने खुद को इतना डरा हुआ कभी महसूस नहीं किया, जितना अब कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, कहना मुश्किल है। एक अंतिम समस्या, जो मैं उठाना चाहता हूँ, वह है राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध। भाजपा समर्थक 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्त करने और इंदिरा गांधी के बाब-बाब अनच्छेद 356 का उपयोग करने पर चर्चा तो करना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे दलों के शासन वाले राज्यों के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं रहा है।

## संक्षिप्त समाचार

राजस्थान में भाजपा  
और कांग्रेस के  
अपने-अपने दावे,  
सीएम भजनलाल  
बोले- विपक्ष के पास  
पीएम चेहरा नहीं

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

जयपुर। लोकसभा चुनाव के  
एिजट पोल पर राजस्थान में  
सत्तारूढ़ दल भाजपा और कांग्रेस  
के नेताओं ने अपने-अपने दावे किए हैं। भाजपा ने जहां एिजट पोल

को सही बताया, वहीं कांग्रेस के  
नेताओं का कहना है कि चार जून  
को यह गलत साबित होंगे। लोकसभा चुनाव के एिजट पोल पर राजस्थान में सत्तारूढ़ दल भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने-अपने दावे किए हैं। भाजपा

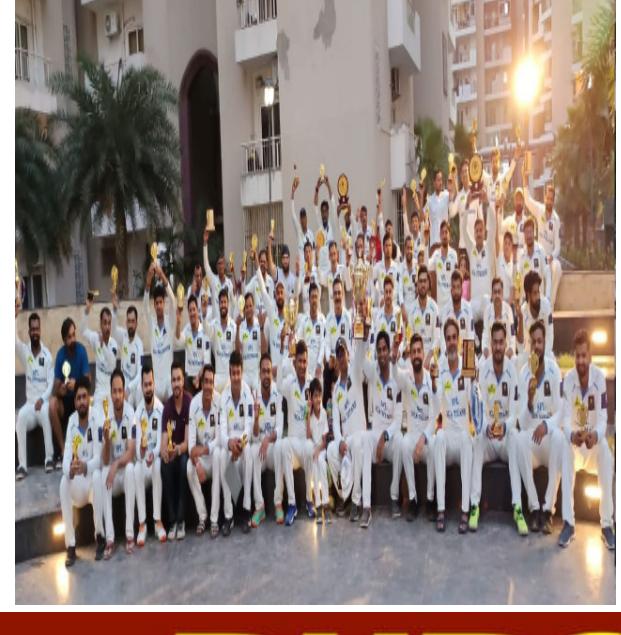
ने जहां एिजट पोल को सही बताया, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चार जून को यह गलत साबित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं उनका गठबंधन कैसा है। दिल्ली में कांग्रेस और आप एकसाथ चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ। वहां अलग-अलग लड़ रहे हैं। विपक्ष हताश और निराश है। सीएम ने कहा, राजस्थान में 2014 और 2019 की तरह सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। अब एक बार फिर सभी 25 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कहा, 'देश में हर कोई कह रहा है कि अब की बार मोदी सरकार चार सौ पार।' वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एिजट पोल को नकारा है। गहलोत ने ट्रॉफी कर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर कब्जा कर अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। सत्तारूढ़

## समृद्धि प्रीमियर लीग : टाइटंस बनी चैम्पियन, स्ट्राइकर ने जीता सिल्वर कप

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

नोडा। आईपीएल की तरफ पर आयोजित किये जा रहे एसपीएल के फाइनल मैच में टाइटंस ने डेस्ट्रॉयर को हराकर कप पहला टाइटल अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी डेस्ट्रॉयर ने 20 ओवर में 163 रन बनाये। डेस्ट्रॉयर की तरफ से सबसे ज्यादा गोल ने 39 रन बनाये। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी टाइटंस ने 19 ओवर में 2 विकेट शेष रहते ही 164 रन बना लिए। टाइटंस के तरफ से कौशल ने 71 रनों की शानदार पारी खेली। मैन ऑफ द मैच टाइटंस के कपानां गौरव को चुना गया। जिन्होंने मात्र 25 बाल में 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली साथ ही 2 विकेट भी लिए। बल्लेबाजी को चुना गया। वहीं सिल्वर कप का मुकाबला स्ट्राइकर और वारियर्स के बीच में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर ने 20 ओवर में 182 रन बनाये। स्ट्राइकर की तरफ से राहुल ढाका

ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाये। वारियर्स की तरफ से कूलदीप ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी वारियर्स की टीम ने अच्छी फाइट करते हुए 181 रन बनाये। स्ट्राइकर ने रोचक मुकाबले को 1 रन से जीत लिए। वारियर्स की तरफ से अभय ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाये। मैन ऑफ द मैच स्ट्राइकर के फाइट करते हुए 181 रन बनाये।



## मानहानि मामले में राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुसीबत

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

गैरहाजिर हुए इस अदालत के बैंगलूरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी

नांदी ने बैंगलूरु की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दायर

गैरहाजिर हुए इस अदालत के सम्पर्क नेता राहुल गांधी। आरोपी नंबर

4 की उपस्थिति के लिए 7 जून को बुलाया गया है। विज्ञानों में

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लाया

था कि भाजपा (उस समय राज्य में सत्ता में थी) सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों

और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्तत ले रही थी। भाजपा

ने अपनी शिकायत में कांग्रेस से नेताओं पर तत्वालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोर्म्हा सहित अपनी पार्टी के सदस्यों का

निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन

फैलाने का आरोप लगाया है। विशेष

अदालत ने राहुल गांधी को शनिवार को वकील ने इंडी गठबंधन की दौरान गांधी के वकील ने राहुल गांधी को छूट देते हुए यह निर्देश दिया है। अदालत

ने कहा, ठियह उपस्थिति से छूट दी, आज उपस्थिति से हो जाती है कि आरोपी नंबर 4 अग्री

सुनवाई की तारीख पर बिना

को हर हाल में उपस्थित रहें।

## चंपई सोरेन बोले- हम झारखंड में 10 सीटें जीत रहे, भाजपा ओडिशा में प्रदर्शन को लेकर खुश

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नेताओं ने नेताओं को बकवास बताते हुए कहा कि वे कम से कम 295

सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि इडियो ब्लॉक के

नेताओं ने नेताओं को बकवास बताते हुए कहा कि वे कम से कम 295

सीटें अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

राज्य में 10 से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। चंपई सोरेन ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे कम से कम 295

सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक के

नेताओं ने नेताओं को बकवास बताते हुए कहा कि वे कम से कम 295

सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इडियो ब्लॉक

से अधिक सीटें जीतेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने

